साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 09-15 सितंबर 2024 वर्ष-10, अंक-21

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

बड़ी उपलब्धिः महाराष्ट्र और राजस्थान को पीछे छोड़कर बना सरताज

एमपी को फिर मिला सोयाप्रदेश का ताज

» देश के कुल उत्पादन में मप्र का योगदान 41.92 प्रतिशत

» भारत के कुल उत्पादन में महाराष्ट्र का योगदान 40.01%

-5.47 मिलियन टन उत्पादन के साथ देश में पहला स्थान

-देश के सोया उत्पादन में राजस्थान का योगदान 8.96 फीसदी

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश ने सोयाबीन उत्पान में अपने निकटतम प्रतियोगी राज्यों महाराष्ट्र और राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए फिर से सोयाबीन प्रदेश बनने का ताज हासिल कर लिया है। भारत सरकार के जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश 5.47 मिलियन टन सोयाबीन उत्पादन के साथ पहले नंबर पर आ गया है। देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में मध्यप्रदेश का योगदान 41.92 प्रतिशत है। महाराष्ट्र 5.23 मिलियन टन के साथ दूसरे नंबर पर । देश के कुल उत्पादन में महाराष्ट्र का योगदान 40.01 प्रतिशत है जबकि राजस्थान 1.17 मिलियन टन उत्पादन के साथ तीसरे नंबर पर है और देश के कुल सोया उत्पादन में राजस्थान का योगदान 8.96 फीसदी है।

दो साल पिछड़ गया था- पिछले दो सालों में मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन में कमी आने से मध्य प्रदेश पिछड़ गया था। वर्ष 2022-23 में महाराष्ट्र 5.47 मिलियन टन उत्पादन के साथ प्रथम स्थान पर था और देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में 42.12 फीसदी का योगदान था और जबकि मध्य प्रदेश 5.39 मिलियन टन के साथ दूसरे नंबर पर था। देश के कुल सोया उत्पादन में योगदान 41.50 प्रतिशत था।

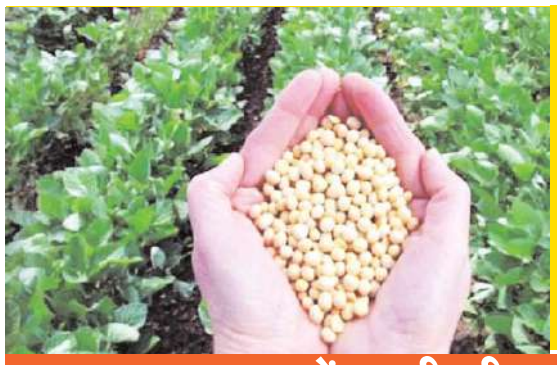

मध्यप्रदेश में सोयाबीन उत्पादन (हजार टन में)	
2019-20	3856
2020-21	3370
2021-22	5392
2022-23	6332
2023-24	6675

2023-24 में 1.7 फीसदी बढ़ा रकबा

प्रदेश में सोयाबीन का रकबा 2022-23 की अपेक्षा 2023-24 में 1.7 फीसदी बढ़ा और क्षेत्रफल पिछले साल 5975 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 2023-24 में 6679 हेक्टेयर हो गया है। सोयाबीन का क्षेत्रफल बढ़ने से उत्पादन भी बढ़ा। पिछले साल 2022-23 में सोयाबीन उत्पादन 6332 हजार मैट्रिक टन से बढ़कर 2023-24 में 6675 हजार मैट्रिक टन हो गया।

पहले नबर पर था महाराष्ट्र

2021-22 में भी महाराष्ट्र 6.20 मिलियन टन उत्पादन के साथ प्रथम स्थान पर था और देश के सोयाबीन उत्पादन में 48.7 फीसदी का योगदान था जबकि मध्य प्रदेश 4.61 मिलियन टन के साथ दूसरे नंबर पर था। देश के कुल उत्पादन में इसका योगदान 35.78 फीसदी था।

राजस्थान तीसरे नंबर

2020-21 में मध्य प्रदेश 5.15 मिलियन टन उत्पादन के साथ पहले स्थान पर रहा था और देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में 45.05 0 फीसदी का योगदान था। इस साल महाराष्ट्र 4.6 मिलियन टन उत्पादन के साथ दूसरे नंबर पर था और राजस्थान तीसरे नंबर पर था।

उतार-चढ़ाव भी दिखा

पिछले वर्षों में सोयाबीन उत्पादन और क्षेत्रफल में उतार-चढ़ाव होता रहा। सोयाबीन के क्षेत्रफल में वर्ष 2018-19की तुलना में वर्ष 2019-20में 14.30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सोयाबीन क्षेत्रफल 2018-19में 5019 हजार हेक्टेयर था जो 2019-20में बढ़कर 6194 हजार हेक्टेयर हो गया। इसी दौरान सोयाबीन का उत्पादन 2018-19में 5809 हजार मिट्रिक टन था जो बढ़कर 2019-20में कम होकर 3856 मैट्रिक टन हो गया। सोया उत्पादन में 33.62 फीसदी की कमी आई।

बदलावः पहले सचिव पद पर तीन वर्ष की थी पात्रता

पंचायत में अब अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता 7 साल

-शैक्षणिक अर्हता पूरी करने का मिलेगा मौका

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश में पंचायत सचिव की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर अब सात वर्ष तक अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने नवंबर 2017 के अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता संबंधी नियम में संशोधन कर दिया है। अब पंचायत सचिव का सेवाकाल के दौरान निधन होने पर तीन वर्ष के स्थान पर सात वर्ष तक अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी। इस अवधि में यदि पात्रताधारी आश्रित की शैक्षणिक अर्हता न हो तो उसे निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त करनी होगी। इसके बाद ही नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित होने और पात्रता के निर्धारण को लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में बहुत शिकायतें थीं। पहले जिले में पद रिक्त न होने पर पंचायत सचिव के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति ही नहीं मिलती थी। विभाग ने पंचायत अधिनियम के नियम 5 (क) के तहत अब यह प्रावधान कर दिया है कि जिस जिले में पंचायत सचिव सेवारत था, वहां की ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिव का पद रिक्त नहीं है, तो उसके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति अन्य जिलों में पंचायत सचिव के रिक्त पद पर दी जाएगी।

प्रदेश में 23 हजार से अधिक पंचायत

साथ ही पात्रता की अवधि 2017 में मृत्यु के तीन वर्ष के भीतर रखी गई थी। इसके कारण कई पात्र आश्रित अनुकंपा नियुक्ति पाने वंचित रह गए थे। जबकि, सामान्य प्रशासन विभाग ने यह अवधि सात वर्ष निर्धारित की है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने भी अब सामान्य प्रशासन विभाग की तरह अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता तीन से बढ़ाकर सात वर्ष कर दी है। इसका लाभ यह होगा कि जो आश्रित शैक्षणिक अर्हता पूरी नहीं कर पाए थे, उन्हें अवसर मिल जाएगा। प्रदेश में 23 हजार से अधिक पंचायतें हैं।

मध्यप्रदेश के हर ब्लॉक का एक गांव बनेगा वृंदावन और निकायों में खुलेंगे गीता भवन

भोपाल। सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। डिप्टी सीएम राजेंद्र कुमार शुक्ल ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वृंदावन ग्राम योजना के तहत हर ब्लॉक से एक ग्राम का चयन किया जाएगा। इस योजना

के अंतर्गत, दूध उत्पादन, उद्यानिकी और औषधीय खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही गीता भवन सभी नगरीय निकायों में खोले जाएंगे। ये भवन वैचारिक अध्ययन केंद्र के रूप में काम करेंगे। पठन-पाठन की सामग्री प्रदान करेंगे। धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भी इन भवनों का उपयोग किया जाएगा। अब रीजनल समिट सागर और रीवा में भी आयोजित की जाएगी। बैठक में मोहासा और सीतापुर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को मंजूरी दी गई है। मोहासा बाबई में रिन्युवल एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों की स्थापना के लिए 227 एकड़ जमीन पर 93.50 करोड़ खर्च किए जाएंगे। मुरैना जिले के सीतापुर में 161.7 एकड़ जमीन पर फुटवियर एसेसरीज और डेवलपमेंट पार्क के रूप में विकास किया जाएगा।

-कैबिनेट का बड़ा फैसलाः सात नई कृषि परियोजनाओं को दी मंजूरी

खाद्य, पोषण के फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़

बागवानी और कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए सरकार ने दिए 2000 करोड़

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए। इसमें बागवानी विकास सबसे अहम है। कैबिनेट ने बागवानी विकास के लिए 860 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के लिए 1,202 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सरकार ने पशुधन के स्वास्थ्य और उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए 1,702 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। साथ ही, कैबिनेट ने खाद्य, पोषण के मद्देनजर फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ की योजना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की जरूरत है। सरकार किसानों के जीवन और आजीविका को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में अब तक पांच बड़े फैसले हो चुके हैं।

» 2,817 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी
» कृषि शिक्षा और प्रबंधन के लिए 2,292 करोड़ रुपए
» पशुधन स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ की योजना
» बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ की मंजूरी
» कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपए मिले
» प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए 1,115 करोड़ रुपए

डिजिटल कृषि मिशन

उक्त फैसलों को मिलाकर किसानों के लिए 12 बड़ी घोषणाएं की जा चुकी हैं। इसी के साथ कैबिनेट ने कृषि शिक्षा और प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 2,291 करोड़ के कार्यक्रम को मंजूरी दी। कैबिनेट ने खाद्य एवं पोषण के लिए फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ की योजना को मंजूरी दी। सरकार ने किसानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए डिजिटल कृषि मिशन पर 2,817 करोड़ खर्च का फैसला किया है।

कृषि शिक्षा और प्रबंधन

वहीं, खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान पर 3,979 करोड़ खर्च किए जाएंगे। केंद्र सराकर 2,291 करोड़ खर्च कर कृषि शिक्षा और प्रबंधन को मजबूत बनाने पर काम करेगी। सरकार टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को लेकर काम करेगी। इसमें 1,702 करोड़ खर्च होंगे, जबकि 860 करोड़ बागवानी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर खर्च किए जाएंगे।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने मंच से दिए सख्त संकेतः अब लापरवाहों पर गिरेगी गाज

शिवराज की फटकार से अफसरों की उड़ी नींद

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों अलग मूड में दिख रहे हैं। वो दर्शनशास्त्र में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, लेकिन आजकल इंजीनियर वाले अंदाज में कृषि मंत्रालय में कसावट ला रहे हैं। बीते कई घटनाक्रम इसकी गवाही दे रहे हैं। वो चाहे कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी रिसर्च बॉडी आईसीएआर यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से जुड़े वैज्ञानिक हों या फिर कृषि मंत्रालय के अधिकारी। कुल मिलाकर वो खेती बाड़ी वाले इस मंत्रालय को अपने हिसाब से पटरी पर दौड़ाने के लिए इससे जुड़े लोगों को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें दो बातें सबसे अहम हैं। एक तो वैज्ञानिकों और किसानों के बीच गैप न हो और दूसरा योजनाओं को इतना पेंचीदा न बनाया जाए ताकि उसका आम लोग फायदा उठा सकें। शिवराज अपने अधिकांश कार्यक्रमों में खेती-किसानी से जुड़े अधिकारियों को उनके काम के तौर-तरीकों को लेकर आइना दिखा रहे हैं। जिसमें वो कामकाज में जटिलता कम करने और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ने की नसीहत दे रहे हैं। ताजा वाकया पूसा में आयोजित कृषि मंत्रालय के एक समारोह का है। समारोह में मंच से ही शिवराज ने नए कृषि सचिव को इस बात के निर्देश दिए कि वो एग्रीकल्चर इफ्रास्ट्रक्चर फंड में सभी सूबों की मैपिंग करें कि किस जगह किस तरह के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है।

हर जगह गोदाम ही क्यों बने

कृषि मंत्री ने इस योजना से जुड़े अधिकारियों से दो टूक शब्दों में कहा कि जहां पर वेयर हाउस की जरूरत है वहीं पर वेयरहाउस बनें. ऐसा न हो कि वो बनकर खाली पड़े रहें। बनवाने वालों को नुकसान हो। इसलिए जहां पर कोल्ड चैन या पैक हाउस की जरूरत है वहां पर इन्हीं चीजों का निर्माण करवाया जाए। हर जगह गोदाम ही बनवाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए राज्यवार पोस्ट हार्वेस्ट यानी फसलोपरांत कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत की मैपिंग करने के निर्देश दिए।

मध्य प्रदेश में गोदाम खाली

शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में सीएम रहते मैंने यह कोशिश की थी कि एआईएफ से ज्यादा से ज्यादा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, जिसका इस्तेमाल करके किसान अपनी आय बढ़ा सकें, लेकिन, अब मध्य प्रदेश में वेयरहाउस इतने हो गए हैं कि वो भर नहीं पा रहे हैं। इसलिए यह ध्यान रखना। जिस सूबे में जिस चीज की जरूरत है उसमें वही बनाना। मध्य प्रदेश में ज्यादा वेयरहाउस बनने से वहां पर एक नई समस्या पैदा हो गई है। हमें लोग बताते हैं कि वेयर हाउस खाली पड़े हैं। इसलिए ऐसा इंफ्रा मत बनाना कि बनवाने वालों को दिक्कत हो जाए।

सिंगल विंडो क्या सिंगल रहती है..

शिवराज ने बातों ही बातों में अधिकारियों को यह संदेश दे दिया है कि कामकाज को सरल करना है। किसी भी योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया को इतना जटिल नहीं बनाना है कि लोग उसका फायदा ही न ले सकें। हम सिंगल विंडो की बात जरूर करते हैं, लेकिन सिंगल विंडो एक और विंडो हो जाती है दस-बारह विंडो के बाद। यहां चले जाओ, वहां चले जाओ...कई लोग तो योजनाओं को लेकर बहुत उत्साह दिखाते हैं, लेकिन बाद में वो जटिलताओं की वजह से सब छोड़कर निकल लेते हैं कि कौन चक्कर में पड़े। दरअसल, शिवराज कृषि निवेश पोर्टल पर टिप्पणी कर रहे थे।

जटिलताओं को खत्म करने का समय

इसी तरह कृषि क्षेत्र में निवेश की प्रक्रियाएं बहुत जटिल हैं। जरूरत ऐसी व्यवस्था बनाने की है कि एक जगह उनको सारी सुविधाएं ठीक से मिल जाएं। कृषि निवेश पोर्टल में यह संभव होगा। भटकना नहीं पड़ेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के लिए योजनाओं का लाभ लेना आसान हो। एग्री इंफ्रा फंड को ही लीजिए। पहले कहते थे कि इस फंड का इस्तेमाल करके आप आटा तो बना सकते हो लेकिन, आटा से ब्रेड नहीं बना सकते। आटा से बिस्किट नहीं बना सकते थे। अब ऐसा नहीं होगा। इस फंड से आटा भी बनेगा और ब्रेड-बिस्किट भी बना सकते हैं।

किसानों से कितना तालमेल

इससे पहले शिवराज ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों और इसका मैनेजमेंट करने वालों को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने कहा था कि भारत की तरक्की में आईसीएआर के अहम योगदान से कभी भी इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन, अब हालात वैसे नहीं हैं, जैसे होने चाहिए। वैज्ञानिक काम करते हैं यह सच है, लेकिन किसान व्यवहारिक काम करता है यह भी सच है। हम आकलन करके देखें कि क्या वैज्ञानिकों और किसानों के बीच पूरा तालमेल है। एक बात सभी जान लें कि मैं कृषि मंत्री की कुर्सी पर बोझ बनने के लिए नहीं आया हूं।

खेती में करेंगे नए प्रयोग

शिवराज ने कहा कि विकसित भारत विकसित कृषि और समृद्ध किसानों के बिना नहीं बन सकता। खेती के बिना भारत का काम नहीं चल सकता। इसलिए हम खेती में कई नए प्रयोग करेंगे। किसान हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। इस बात का एहसास कोविड के वक्त हुआ, जब सारी गतिविधियां बंद थीं लेकिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उस दौरान खेती ने ही भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने का काम किया।

दिल्ली के डिपो से नीलाम होगी सागौन की लकड़ी

मप्र के सागौन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाएगी सरकार

6.50 करोड़ रुपए की है सागौन की इमारती लकड़ी

भोपाल। जागत गांव हमार

मोहन सरकार अब मध्य प्रदेश के सागौन को राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने प्रयास करेगी। इसके लिए मध्य प्रदेश के सागौन की दिल्ली के डिपो में उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। उच्च गुणवत्ता के सागौन को मप्र से दिल्ली के डिपो रखा जाएगा, ताकि क्रेता यहां आकर सागौन की अलग-अलग किस्म और उसकी विशेषताओं से अवगत हो सकें। इस बार दिल्ली डिपो में मध्य प्रदेश की 6.50 करोड़ रुपए की सागौन की इमारती लकड़ी नीलाम की जाएगी। दो सितंबर को सागौन काष्ठ की नीलाम होगी। इसकी सूचना वन विभाग ने जारी की है। तय मूल्य से अधिक जो बोली लगाएगा, उसे यह सागौन काष्ठ दे दी जाएगी।

बैतूल के सागौन की देशभर में मांग- यह सागौन काष्ठ मध्य प्रदेश के वनों से विदोहन के जरिए लाई गई है। यह 400 घनमीटर सागौन के लट्ठे हैं। इनमें बैतूल जिले में उत्पन्न सागौन की लकड़ी की देशभर में मांग है। यहां के जंगल में कई खूबियों वाली इस प्रजाति के सौ साल पुराने वृक्ष भी मौजूद हैं। यहां का सागौन मध्य प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल है। तेलीय सागौन की लकड़ी अच्छी गुणवत्ता के चलते पसंद की जाती है। सागौन में घुन नहीं लगता जिसके चलते इसकी अधिक मांग होती है।

मप्र में उत्तम श्रेणी के सागौन

प्राकृतिक रूप से सागौन भारत के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में मुख्य रूप से पाया जाता है। प्रदेश में सागौन मुख्यतः होशंगाबाद, बैतूल, खंडवा, छिंदवाड़ा, सिवनी, सागर और मंडला में पाया जाता है।

खिलौना उद्योग में भी डिमांड

सागौन की लकड़ी की खिलौना उद्योग में भी काफी मांग है। बुधनी में खिलौना क्लस्टर से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर बढ़े हैं तो वहीं यहां के लकड़ी के खिलौनों की देशभर में मांग भी बढ़ी है। इसके चलते ही अब देश के अन्य राज्यों ने भी मध्य प्रदेश के सागौन में रुचि दिखाई है। एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) में शामिल सागौन को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

रघुवीर ने खेती कर एक साल में कमाए दस लाख रुपए

उन्नत तरीके से खेती-किसानी में है मुनाफा ही मुनाफा

भोपाल। जागत गांव हमार

सोच बड़ी होनी चाहिए। रास्ते अपने आप मिलते चले जाते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ऐसे ही प्रगतिशील विचार लिये किसान रघुवीर सिंह ने पुरानी खेती-बाड़ी में कुछ नया करने का सोची। पहले कुछ संकोच भी हुआ कि यदि नये ढंग से खेती सफल न हुई, तो परिवार कैसे पालेंगे, पर रघुवीर सिंह ने जोखिम उठाया और स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति से खेती करने लगे। नई सोच, नया सबेरा लेकर आती है। रघुवीर को भी अपनी प्रगतिशीलता का लाभ मिला। उन्होंने स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति से एक हेक्टेयर में लहसुन की खेती की। मात्र एक हेक्टेयर में लहसुन की फसल से ही रघुवीर सिंह को अंततः 10 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ। पानी की बचत हुई, सो अलग। फसल मुनाफे की यह कहानी नीमच जिले की है। रघुवीर सिंह एक साधारण किसान हैं। नीमच के समीप आंवलीखेडा गांव में रहते हैं। गांव के अन्य किसानों की तरह पहले वे भी पुराने तौर-तरीकों से खेती करते थे। पर अब उन्होंने खेती-बाड़ी के पुराने तरीकों को त्याग दिया है। नई सोच अपनाकर वे स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली से खेती करके और किसानों के लिये नजीर पेश कर रहे हैं। वर्ष 2022-23 में रघुवीर सिंह ने मिनी स्प्रिंकलर संयंत्र के लिये उद्यानिकी विभाग से संपर्क किया। पर ड्राप-मोर क्राप योजना के अंतर्गत उद्यानिकी विभाग ने रघुवीर सिंह को 51 हजार का अनुदान दिया और उसके खेत में स्प्रिंकलर संयंत्र स्थापित कराने में मदद भी की।

दूसरे किसान भी स्प्रिंकलर से सिंचाई पद्धति से जुड़ने लगे

स्प्रिंकलर लगाने के बाद रघुवीर को तीन तरह से बचत होने लगी। पानी बचने लगा। सिंचाई के लिये मजदूर भी नहीं लगाने पड़े, इससे पैसों की बचत हुई। लहसुन की फसल में कीट प्रकोप की भी रोकथाम हो गई। साथ ही लहसुन की क्वालिटी भी अच्छी हुई। बड़े आकार का लहसुन उत्पादन देखकर रघुवीर सिंह गद्गद हो गये। एक हेक्टेयर में 130 क्विंटल लहसुन हुआ। नीमच मंडी में ले जाकर बेचने पर रघुवीर को कुल 13 लाख रूपये मिले। फसल लागत घटाने पर रघुवीर को अविश्वनीय रूप से 10 लाख रूपये शुद्ध मुनाफा हुआ। रघुवीर के मुनाफे से प्रेरित होकर अब दूसरे किसान भी स्प्रिंकलर से सिंचाई पद्धति से जुड़ने लगे हैं। कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने में यह पद्धति बाकई कारगर साबित हो रही है।

पशुपालकों का एटीएम छोटा पशु

गाय-भैंस के बाद तेजी से बढ़ने लगा बकरी पालन

भोपाल। जागत गांव हमार

गाय-भैंस सुबह-शाम में ही दूध देती है, जबकि पशुपालकों का एटीएम बने पशु का दूध कभी भी दोह सकते हैं। अगर बिक्री करनी हो तो एक घंटे में नकद बिक जाता है। पशु का मैन्योर एडवांस रुपयों में बिक रहा है। शायद इसीलिए इस छोटे पशु को पशुपालकों का एटीम कहा जाता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पंजाब में इस पशु का पालन करने वालों को गरीब समझा जाता था। इसलिए इस पशु को गरीब की गाय के नाम से भी जाना जाता है। ये गरीब की गाय और कोई नहीं महात्मा गांधी की भी चहेती रही बकरी है। आज देश में गाय-भैंस के बाद सबसे ज्यादा बकरी पालन हो रहा है। दूध-मीट की डिमांड को देखते हुए अब चार-पांच बकरियों के पालन से बढ़कर बड़े-बड़े गोट फार्म खुल रहे हैं। आज यही गरीब की गाय पशुपालकों को चार तरीके से मुनाफा करा रही है। मीट-दूध से तो इनकम होती ही है, साथ ही बकरी के बच्चे और एडवांस रकम के साथ मैन्योर (मेंगनी) बेचकर भी इनकम हो रही है। खास बात ये है कि हर साल मीट और दूध की डिमांड बढ़ रही है। घरेलू बाजार ही नहीं एक्सपोर्ट का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। पशुपालन के लिए बैंक से लोन लेने वालों में भी सबसे ज्यादा आवेदन बकरी पालन के लिए आ रहे हैं।

बकरी के दूध पर काम कर रहीं बड़ी कंपनियां

इंडियन डेयरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और अमूल के पूर्व एमडी डॉ. आरएस सोढ़ी का कहना है कि डेयरी के बड़े प्लेयर की नजर बकरी के दूध पर है। बाजार में डिमांड भी है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी बकरी का दूध कलेक्शन करने में आती है। लेकिन जल्द ही ये परेशानी दूर हो जाएगी। बड़े बकरी फार्म की संख्या अभी कम है। लेकिन कई बड़ी कंपनियों ने बड़े बकरी फार्म की शुरुआत कर दी है। अकेले गुजरात में ही दो से तीन बड़े बकरी फार्म पर काम चल रहा है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भी बड़े फार्म पर काम चल रहा है।

बच्चों की दवाई बनाने में इस्तेमाल

केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान (सीआईआरजी), मथुरा के डायरेक्टर मनीष कुमार चेटली का कहना है कि खासतौर से बच्चों में बकरी का दूध बहुता फायदा पहुंचाता है। यही वजह है कि यूरोप में बच्चों के लिए बनने वालीं 95 फीसद दवाइयों में बकरी का दूध इस्तेमाल किया जाता है। बकरी के दूध में वीटा क्रेजिन होता है। जबकि गाय के दूध में अल्फा क्रेजिन पाया जाता है। इसलिए बकरी का दूध पीने से बच्चों को किसी भी तरह की एलर्जी नहीं होती है।

बड़ा है बकरों के मीट का बाजार

वैसे तो देश में बकरियों की 40 नस्ल हैं। इसमे 7 नस्ल ऐसी हैं जो दूध के लिए पाली जाती हैं। जबकि ब्लैक बंगाल, बीटल और बरबरी मीट-दूध दोनों के लिए ही पाली जाती है। जमनापरी और जखराना नस्ल को मीट के लिए ही पाला जाता है। देश में बकरों की पांच ऐसी नस्ल हैं जो मीट के लिए देश ही नहीं विदेशों में भी पसंद की जाती हैं। बकरीद साल का एक बड़ा बाजार है बकरों के लिए। इसके अलावा दुर्गा पूजा भी। मीट एक्सपोर्ट की बात करें तो इसे और बढ़ाने के लिए अब बकरी पालन में ऑर्गेनिक चारे पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि होता ये है कि एक्सपोर्ट के दौरान मीट की केमिकल जांच होती है। हैदराबाद का एक संस्थान यह जांच करता है। कई बार ऐसा हुआ कि जांच के बाद मीट कंसाइनमेंट लौटकर आ जाता है। यह इसलिए होता है कि बकरों को जो चारा खिलाया जाता है उसमे कहीं न कहीं पेस्टीसाइड का इस्तेमाल हुआ होता है। लेकिन अब बकरी पालन के दौरान ऑर्गेनिक चारा उगाने की सलाह दी जाती है। सीआईआरजी तो इस पर रिसर्च भी कर चुका है।

बकरों का वजन बढ़ाने पर चल रही रिसर्च

एक बकरे में से जितना ज्यादा मीट निकलेगा तो मीट बेचने वाले को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए सीआईआरजी में एक रिसर्च चल रही है। ये बकरों का वजन बढ़ाने से संबंधित रिसर्च है। जीन एडिटिंग नाम की इस रिसर्च से किसी भी नस्ल के बकरे और बकरियों के जीन में एडिटिंग कर उनका वजन बढ़ाया जा सकेगा। सीआईआरजी के सीनियर साइंटिस्ट एसपी सिंह के मुताबिक अगर किसी भी नस्ल के बकरे का अधिकतम वजन 25 किलो है तो इस रिसर्च से उसका वजन 40 से 50 किलो तक किया जा सकेगा।

पूरे साल कमाई कराता ब्रीडिंग सेंटर

गोट एक्सपर्ट की मानें तो अगर ब्रीडिंग सेंटर चलाकर बकरा पालन किया जाए तो ज्यादा मुनाफा होता है। इसका तरीका ये है कि आप जगह और अपनी सुविधा अनुसार बकरियां और ब्रीडर बकरा रखकर उनसे बच्चे ले सकते हैं। जैसे अगर 100 बकरी हैं तो मानकर चलें कि छह महीने में आपको 150 बच्चे मिलेंगे। उसमे बकरियां भी होंगी। इसमे से अच्छे बच्चे छांटकर उन्हें ब्रीडिंग के लिए रख सकते हैं। कुछ 150 बच्चों में से 90 या 100 बकरे मिल जाएंगे। इन्हें आप पूरे एक साल या डेढ़ साल तक, जब भी बकरीद हो उन्हें खिला-पिलाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह अच्छी नस्ल के बकरे तैयार हो जाएंगे। प्योर ब्रीड होने के चलते देखने में भी खूबसूरत होते हैं। बकरीद के दौरान वजन से ज्यादा खूबसूरती के दाम मिलते हैं।

25 बकरी पालकर ऐसे कर सकते हैं शुरुआत

मथुरा, यूपी में बकरी पालन कर रहे और सीआईआरजी के गेस्ट ट्रेनर और गोट एक्सपर्ट राशिद बताते हैं कि अगर आप 20 से 25 बकरे-बकरियों के साथ गोट फार्मिंग शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको 20 स्क्वायर फीट लम्बे और 20 फीट चौड़े हॉल की जरूरत होगी। इस साइज के हॉल को तैयार कराने में आज के बाजार रेट के हिसाब से करीब 150 से 175 रुपए स्क्वायर फीट का खर्च आएगा। इसके साथ ही बिजली के उपकरण और उनकी फिटिंग का खर्च अलग से है। इस प्लान के तहत 20 बकरियों के साथ पांच बकरे पाले जाएंगे। 20 बकरी और पांच बकरों के पालन पर तीन से 3.50 लाख रुपए तक की लागत आएगी। अगर मुनाफे की बात करें तो एक साल में एक बकरी पर 5.5 हजार से लेकर छह हजार रुपए प्रति बकरी मुनाफा होगा।

एडवांस में कमाई कराती है मेंगनी

बकरी पालकों की मानें तो अगर किसी बकरी फार्म में 200 बकरी हैं तो यह तय मान लें कि 25 से 30 दिन में एक ट्राली मेंगनी जमा हो जाती है। अगर मेंगनी की इस ट्राली को बेचा जाए तो यह 1200 रुपए से लेकर 1400 रुपए तक की बिक जाती है। खरीदार एडवांस में पैसा दे जाते हैं। वहीं अगर हम इससे वर्मी कम्पोस्टा बनाकर बेचते हैं तो यह आठ से 10 रुपए किलो तक बिकती है। वर्मी कम्पोस्टर बनाने में थोड़ी मेहनत जरूरत लगती है, लेकिन इससे मुनाफा अच्छा हो जाता है।

दूधारू बकरियां

2020-21	3.63
2021-22	3.96
2022-23	4.19

नोट-आंकड़े करोड़ में

बकरी का दूध उत्पादन

2020-21	62.62
2021-22	66.02
2022-23	75.99

नोट-आंकड़े लाख टन में

मीट के लिए काटे गए बकरे

2020-21	10.65
2021-22	11.13
2022-23	12.34

नोट-आंकडे करोड़ में

बकरा मीट उत्पादन

2020-21	12.12
2021-22	12.66
2022-23	14.13

नोट-आंकड़े लाख टन में

पांच राज्यों में दुधारू बकरियां

राज्य	संख्या
राजस्थान	89
उत्तर प्रदेश	44
मध्य प्रदेश	45.35
बिहार	45
महाराष्ट्र	38

नोट- आंकड़े लाख में

पांच राज्यों ज्याद दूध

राज्य	उत्पादन
राजस्थान	31
उत्तर प्रदेश	13.13
मध्य प्रदेश	10.12
गुजरात	3.63
महाराष्ट्र	3.45

आंकड़े लाख टन में

नोट- सभी आंकड़े केन्द्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के हैं।

मछलियों का पोषण में महत्व

» डॉ. माधुरी शर्मा
» डॉ. विमल प्रसन्ना मोहंती
» महेंद्र सिंह
1. मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय, नादेपचिविवि, जबलपुर मप्र.
2 पूर्व एडीजी, अंतर्देशीय मत्स्य पालन, आईसीएआर, नई दिल्ली

दुनिया पर निरन्तर बढ़ रहे जनसंख्या दबाव से निपटने के लिए खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाना तो आवश्यक है, परन्तु इसके साथ-साथ दिन-प्रतिदिन बढ़ रही कुपोषण एवं बेरोजगारी की समस्या का समाधान भी अत्यन्त आवश्यक हो गया है। इन समस्याओं को सुलझाने का एक तरीका यह है कि प्राकृतिक संसाधनों से अधिक से अधिक मछलियां पकड़ी जायें और दूसरा तरीका है कि इन मछलियों का पालन करके अधिक-से अधिक उत्पादन किया जाए।

मछली पालन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार की कई योजनाएं हैं जिनके माध्यम से लोगों को मछली पालन के लिए जागरूक व प्रेरित किया जा रहा है। मछली पालन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को बढ़ाने क लिए मई 2020 कें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रांरभ की गई है। यह योजना अब तक की सबसे बड़ी योजना है, जिसमें 20050 करोड़ रुपये का बजट 5 वर्षों के लिए दिया गया है। मछलियों का प्रयोग मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही भोजन के रूप में किया जा रहा है। भोजन की पौटिकता के अतिरिक्त मछलियों का माँस स्वादिष्ट एवं सुपाच्य होती है। ताजी अवस्था के अतिरिक्त परिरक्षित अवस्था में भी मछलियों की खपत भोजन के रूप सुपाच्य होता है। कृषि के अन्य आयामों की तुलाना में मत्स्य उत्पादन हेतु न केवल कम ऊर्जा की खपत होती है, अपितु लागत भी अपेक्षाकृत कम आती है।

मछलियों का मांस पोषक, स्वादिष्ट एवं सुपाच्य होता है। भारतीयों के लिए तो मछलियॉ सर्वोत्तम संपूरक भोजन का कार्य करती हैं, जिनमें प्रोटिन, वसा, विटामिन ।ए क्ए म् तथा ज्ञ के अतिरिक्त कैल्शियम, फॉस्फोरस तथा लौह जैसे खनिजों की उपयोगी मात्रा पायी जाती है। मछलियों के माँस में कार्बोहाइड्रेड की मात्रा बहुत कम पायी जाती है। मछलियों के माँस दस अनिवार्य अमीनो अम्ल पाये जाते हैं, जिनमें लाइसिन अमीनो अमल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हिस्टिडीन अमीनो अम्ल की प्रचुर मात्रा इनके माँस इनके माँस को विशिष्ट माँसल सुंगध प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त मछलियों में पायी जाने वाली वसा में बहुअसंतृप्त अमीनो अम्लों की प्रचुर मात्रा पायी जाती है, जो इसे वनस्पाति की तुलना में अधिक उपयोगी बनाती है। भारत जल संसाधनों एवं जैव विविधता से समृध्य है। नेषनल व्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिर्सोसिस के डाटा वेस के अनुसार भारत में 2,508 देशज (इंडिजनेस) मछलियों की प्रजातियॉ पाथी जाती है जिसमें 877 स्वच्छ जलीय 113 ब्रेकिश (खारे) पानी की तथा 1,518 समुदी जल की प्रजातियॉ सम्मिलित है। इसके साथ 291 विदेशी प्रजातियों की मछलियॉ भी पायी जाती है। इसके साथ 2934 क्रस्टेऊसिया वर्ग की प्रजातियॉ पायी जाती हैं जिसमें 2430 समुद्री व 504 स्वच्छ जलीय प्रजातियॉ सम्मिलित हैं इसके अतिरिक्त 5070 प्रजातियां मोलस्का संघ की पायी जाती हैं जिसमें 3,370 समुद्री व 1,700 स्वच्छ जलीय प्रजातियॉ है।

राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर विशेष

भाकृअनुप के मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थानों ने विभिन्न आवासों की खाद्य मछलियों की पोण संरचना के बारे में जानकारी का खजाना तैयार की है। इनके द्वारा 115 से अधिक प्रजातियों के लिए पोषण संबंधी जानकारी तैयार की गई है और यह जानकारी ओपन एक्सेस के तहत उपलब्ध हैं। न्यूट्रीफिष इंडिया नाम का डेटाबेस संक्षेप में इसे न्यूट्रीफिशइन भी कहते हैं। इस डेटाबेस में महत्वपूर्ण खाद्य मछलियों की समीपस्थ संरचना, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और सूक्ष्म पोकृक / घटक तत्वों की जानकारी षामिल है। यह जानकारी उपभोक्ताओं, उत्पादकों, उद्यमियों, आहार विशेषज्ञों, चिकित्सकों और योजना बनाने वालों के लिए उपयोगी है।

न्यूट्रिस्मार्ट प्रजातियां वे प्रजातियां है, जो ओमेगा-3 पॉली अनसेचुरेटेड फैटीएसिड (पीयूएफए), खनिज और मिनरल जैसे कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है। मछली गुणवत्ता वाली पशु प्रोटीन का अच्छा स्त्रोत है। मछली में प्रोटीन की मात्रा 13 से 22 प्रतिशत के बीच होती है। समुद्री मछलियाँ विषेष रूप से ओमेगा-3 पीयूएफए (ईपीए और डीएचए) से भरपूर होती है। ठंडे पानी की प्रजातियां भी पीयूएफए से भरपूर होती हैं। अध्ययन की गई सभी प्रजातियों-हिल्सा और आइल सार्डिन में तेल की उच्चतम मात्रा क्रमश: 10.2 और 8.5 प्रतिशत है। मीठे पानी की प्रजातियों में, कोई (अनाबास टेस्टुडिनियस) और पेंगवा (ओस्टियोब्रोमा बेलंगेरी) में उच्च मात्रा में तेल होता है। छोटी देशी मछलियों में सूक्ष्म पोषक तत्व अच्छी मात्रा में मिलते हैं, जैसे मोला और पुंटि (पुंटियस सोफोरे) वसा में घुलनशील विटामिन और कई ट्रेस तत्व भरपूर मात्रा में पाये जाते है ।

वर्षा ऋतु में मुर्गियों का प्रबंधन

» डॉ. लक्ष्मी चौहान
» डॉ. अनिल शिंदे
» डॉ. गिर्राज गोयल
» डॉ. वैशाली खरे
पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर, मप्र

वर्तमान में मुर्गीपालन किसानों के आजीविका का प्रमुख साधन बना है। मुर्गीपालन कम लागत में अधिक आय एवं आसानी से इनका रखरखाव के कारण आज के इस दौर में बड़े व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। बेरोजगार युवा और महिला भी इसे आसानी से कर सकते हैं। मुर्गीपालन में तकनीकी जानकारी की आवश्यकता होती है। जैसे कि अलग-अलग ऋतुओं में मुर्गीपालन में कौन-सी सावधानियां रखना चाहिए, जिससे होने वाली हानि को कम या उससे बचा जा सकता है। बरसात शुरू होने से पहले मुर्गी आवास, आहार की व्यवस्था बनानी चाहिए।

आवास प्रबंधन: सबसे पहले मुर्गी घर की मरम्मत कर लेनी चाहिए जैसे कि छत की मरम्मत, दाना घर की मरम्मत आदि। मुर्गियों का शेड ऊंची एवं समतल जगह होना चाहिए और बारिश के दिनों में बारिश का पानी अंदर नहीं जाना चाहिए। बारिश का पानी शेड के आसपास एकत्रित नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें जीवाणु, विषाणु पनपते हैं और वह कई रोगों का कारण बन सकते हैं। यदि मुर्गी का शेड साधारण बना हो और ऊपर से खुला हो तो ऊपर से प्लास्टिक या पॉलिथिन बिछानी चाहिए ताकि बारिश का पानी अंदर प्रवेश न कर सकें। जाली की तरफसे पानी अंदर न जाए इसलिए पॉलिथिन से बंद करना चाहिए और धूप निकलते या बारिश बंद होने पर उसे खोलना भी चाहिए।

बिछावन/बुरादा प्रबंधन: बारिश के दिनों मे बुरादे का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। बरसात शुरू होने से पहले मुर्गी घर का बुरादा बदल देना चाहिए और बाद में अगर बारिश में गिला हो जाए तब सूखा बुरादा मिलाते रहना चाहिए या उसमें सफेद चुना 1 किग्रा/1 वर्ग मी. जगह के बुरादे में मिला देना चाहिए जिससे गिले बुरादे की नमी कम हो जाए। बुरादे में 20-25 प्रतिशत नमी होनी चाहिए। ज्यादा नमी होने पर कई तरह के रोगों को निमंत्रण मिलता है। जैसे कि कॉक्सीडीओसिस और अन्य फफूंद संक्रामक रोग। बिछावन के लिए मुख्यत: लकड़ी एवं धान का भूसा प्रयोग किया जाता है। बरसात के दिनों में विशेषत: लकड़ी का बुरादा प्रयोग करना चाहिए क्योंकि यह पूरी तरह से नमी को सोख लेता है।

आहार प्रबंधन: बरसात में दाने के भंडारण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर दाने में 10 प्रतिशत से अधिक नमी हो तो उसमें फफूंद लगने की संभावना बढ़ जाती है और बीमारियां शुरू हो जाती है। इसलिए दाने का भंडारण सूखी और जमीन से ऊंची जगह पर करना चाहिए एवं छत से उस पर पानी नहीं टपकना चाहिए। मुर्गियों को साफ-सुथरा पानी पीने के लिए देना चाहिए एवं पानी के स्त्रोतों को जैसे कि कुओं एवं तालाबों में नि:संक्रामक का छिड़काव कर देना चाहिए और इसके साथ-साथ अनावश्यक पानी के गड्ढों की मरम्मत कर देनी चाहिए।

स्वास्थ्य प्रबंधन: बरसात में दिन के मौसम में कई तरह के बदलाव आते हैं। कभी बारिश, ठंड और गर्मी भी लगने लगती है। इसी कारण से मुगिज्यों में कई तरह की बीमारियों का खतरा रहता है। विशेषत: कॉक्सीडीओसिस (खून के दस्त) जो कि बुरादे की नमी के कारण होते हैं और इसमें मृत्यु दर भी काफी बढ़ जाती है। इस बीमारी से बचाव के लिए बुरादा सूखा रहना जरूरी होता है एवं मुर्गियों के दानों में कॉक्सीडीओस्टेट मिला सकते हैं या बीमार मुर्गियों को एम्प्रोजोल नामक दवाई पशु चिकित्सक के निर्देशानुसार पिलानी चाहिए।

मुर्गियों में बरसात के दिनों में परजीवी विशेषत: आंतरिक परजीवी का प्रकोप दिखता है। ऐसे में 21 दिनों के अंतराल से मुर्गियों को दो बार आंतरिक परजीवीनाशक दवाई पिलानी चाहिए। कई बार घर के पिछवाड़े में पलने वाली मुर्गियों में बारिश का पानी पीने की वजह से जीवाणु जन्य रोगों के लक्षण जैसे- दस्त लगना, कमजोर होना, सर्दी-जुकाम आदि दिखाई दें तब उन्हें सही एन्टीबॉयोटिक दवाई पानी में घोलकर पिलानी चाहिए। अंत में बरसात में आवास, बिछावन, आहार एवं स्वास्थ्य का प्रबंधन किया जाए तो निश्चित ही मुर्गी पालन एक लाभकारी व्यवसाय हो सकता है।

घोड़ों में खुजली रोग का कारण और उसका उपचार

» डॉ. शिवम सिंह मेहरोत्रा
» डॉ. आर.के बघेरवाल
» डॉ. हेमंत मेहता
» डॉ. मुकेश शाक्य
पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय महू, मध्यप्रदेश

घोड़ों में खुजली होना आम बात है। घोड़ों में खुजली (जिसे प्रुरिटस भी कहा जाता है) एक सामान्य लक्षण है जो कीड़े के काटने, त्वचा संक्रमण या एलजीज़ का संकेत हो सकता है। हालांकि यह कभी-कभार ही जानलेवा होता है, लेकिन खुजली के लिए तुरंत पशु चिकित्सक की मदद की ज़रूरत होती है, क्योंकि खुजली से जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। समय के साथ अनुपचारित संक्रमण और भी बदतर हो सकता है, और घोड़े खुरदरी सतहों पर रगड़कर अपनी त्वचा को और अधिक परेशान या नुकसान पहुंचा सकते हैं।

घोड़ों में खुजली रोग कीटों द्वारा होता है, जिसमें त्वचा लाल रंग की हो जाती है। बाल उड़ जाते हैं तथा चमड़ी मोटी हो जाती है। यह रोग सारकोप्टिक, सौरोप्टिक तथा कोरियोप्टिक माइट्स द्वारा होता है।

कारण: यह एक प्रकार के बाहय परजीवी खुजली कीट (माइट्स) द्वारा होता है। जो निम्न तीन प्रकार के होते हैं। सारकोप्टिक स्केबियाई , सोरोप्टिक , कोरियोप्टिक ये कीट एक से दूसरे जानवर में सम्पर्क, साफ करने के उपकरण, बिछावन, घर की धूल, झूल, झालन आदि से फैलते हैं।

रोग व्यापकता: प्राय: खुजली रोग घोड़ों में एक दूसरे से संपर्क व सफाई व खुजली करने के उपकरण आदि से भी यह घोड़ों में फैलता है। यह सभी उम्र के घोड़ों को प्रभावित करता है तथा सभी प्रजाति के घोड़े इससे प्रभावित होते हैं।

लक्षण: मुख्य रूप से मुंह पर, आंखों के पास, कान में, कान के नीचे, पीठ व टांगों पर खुजली के लक्षण दिखायी देते हैं। गंभीर खुजली के कारण घोड़ा अधिक जोर से खुजलाता है, जिससे त्वचा पर चोट या क्षति हो सकती है। घोड़े की त्वचा में खुजली होती है वह किसी बाहय कठोर चीज से खुजली करता है व एक दूसरे से भी रगड़ते हैं, जिससे त्वचा में चोट लगती है व कभी-कभी वहां से खून भी निकलता है। त्वचा मोटी हो जाती है व प्रभावित त्वचा से बाल उड़ जाते हैं। काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं।

पूंछ रगड़ना खुजली की एक आम प्रतिक्रिया है, जिससे पूंछ घिस सकती है या बाल झड़ सकते हैं। घोड़ों द्वारा वस्तुओं से खुद को खरोंचने से उनके शरीर पर मौजूद बालों के हिस्से भी झड़ सकते हैं या उनके अयाल के हिस्से घिस सकते हैं।

निदान: इस रोग का निदान लक्षणों तथा विकृति से किया जाता है। पूर्ण निदान के लिए त्वचा की छीलन का सूक्ष्मदर्शी द्वारा परीक्षण किया जाता है, जिसमें खुजली कीट को देखा जाता है। खुजली का विस्तृत इतिहास निदान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, जिसमें शामिल हैं।

खुजली कितने समय पहले शुरू हुई थी, यह कितनी नियमितता से होता है , घोड़े के जीवन या पर्यावरण में कोई भी हालिया परिवर्तन, आजमाए गए उपचार या घरेलू उपचार, इस समय घोड़े के संपर्क में आने वाले जानवर, अन्य निदान में शामिल हैं: त्वचा खुरचना , सूक्ष्मदर्शी से बालों की जांच ,त्वचा बायोप्सी , जीवाणु या कवक संवर्धन

उपचार: उपचार अंतर्निहित कारण पर निर्भर करता है, और इसमें एलर्जीन इम्यूनोथेरेपी, एंटीबायोटिक्स, एंटीपैरासिटिक दवाएं और खुजली को कम करने के लिए दवा शामिल हो सकती है। अंतर्निहित कारण के आधार पर निवारक उपाय भी सुझाए जा सकते हैं, जैसे कि कीट विकर्षक, घोड़े के वातावरण से एलर्जी को हटाना, या नियमित रूप से कृमिनाशक दवा देना।

उपचार के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है जिसमें 'सैविन' या 'मैलाथियान' या 'पैस्टोवैन' प्रमुख हैं। पानी में दवा का घोल बनाकर ये मशीन से प्रभावित त्वचा पर छिड़काव कर देना चाहिए। वैसे त्वचा में या मांस पेशी में आइवरमैक्टिन का टीका लगाने से भी खुजली में आराम मिलता है।

बचाव व रोकथाम: बचाव के लिए अच्छे घोड़ों को बीमार से अलग रखना चाहिए। - इनके उपकरण, काम करने वाले व्यक्ति आदि भी अलग रहने चाहिए। - बचाव के लिए आइवरमैक्टिन के टीके लगवाने चाहिए। जिससे बाह्य व अन्त: परजीवी सभी से बचाव हो जायेगा। - घोड़े मलिक को त्वचा की रखरखाव के लिए अच्छे से मालिश (ग्रूमिंग) करनी चाहिए। - घोड़े को अच्छा राशन और साफसुथरा पीने का जल प्रदान करें। - यह समस्या के लक्षण दिखने पर तुरंत ही पशु चिकित्सक से सलाह अवश्य लेना चाहिए।

ट्रैक्टर युग में भी फायदेमंद है बैलों से जुताई

मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती... यह गीत आपने जितनी बार भी सुना होगा आप के दिमाग में एक ही चित्र उभर कर आता है। वह है खेत में हल और बैल के साथ काम करता हुआ एक किसान। लेकिन, आधुनिक होती खेती के दौर में अब हल और बैल से खेत की जुताई के नजारे कम ही दिखते हैं। इनकी जगह ट्रैक्टर से जुताई समेत अन्य उपकरणों ने ले ली है। वर्तमान में देश में प्राकृतिक खेती को लेकर हो हल्ला मचा हुआ है।

मौजूदा समय में भी कई ग्रामीण क्षेत्र के किसान पारंपरिक तरीके से ही दो बैलों की जोड़ी और हल के साथ खेतों की जुताई कर रहे हैं। अन्नदाता की यह परंपरा शायद अपने अंतिम दौर में है। पारंपरिक तरीके से खेती का यह स्वरूप अब विलुप्त होता जा रहा है। आपको बता दें कि मिट्टी की गुणवत्ता को बनाने में जितना अधिक हल-बैल से जुताई करने में योगदान होता है वह किसी अन्य प्रकार के हल में मौजूद नहीं है, लेकिन समय की बचत के कारण अब तकनीकी रूप से किसान आधुनिक मशीनों की ओर रूख कर रहे हैं।

हल बैल से खेती करने के फायदे : हल और बैल से खेती करने में खेत की मिट्टी में मौजूद सभी पोषक तत्व और जीव प्राकृतिक तौर पर फसलों की ग्रोथ में मदद करते हैं। खेत में पाए जाने वाला फ्रसल मित्र केंचुआ हो या अन्य दूसरे कीट खेत में पहले के समान ही जुताई के बाद भी बने रहते हैं, जो बीज के अंकुरण में बड़ी भूमिका निभाते हैं।

हल-बैल से जुताई से इन फसल मित्रों के साथ ही उगने वाली लाभदायक घास को निचले हिस्से से काटता है, जिससे वह घास मिट्टी में मिलकर सड़ जाती है और खाद का काम करती है। इससे फसल में खाद का इस्तेमाल भी न्यूनतम हो जाता है। उस दौर में भी रासायनिक खादों का इस्तेमाल नहीं होता था, तब इस तरह की घास और पौधे खेत की मिट्टी में सड़कर खाद बन जाया करते थे।

आधुनिक तकनीक से होने वाले नुकसान

- आधुनिक खेती में इस्तेमाल होने वाले रसायनों और उर्वरकों से मिट्टी की क्वालिटी में कमी आती है। - मशीनों से खेत की जुताई करने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होती है। - ट्रैक्टर से खेतों की जुताई करने से खेत में पाए जाने वाले फसल मित्र नष्ट हो जाते हैं। - प्राकृतिक तौर पर उगे खरपतवार, जो फसलों के लिए खाद का काम करते हैं वो भी नष्ट जो जाते हैं। - आधुनिक तकनीक से खेती करने से सबसे अधिक नुकसान पार्यावरण को है।

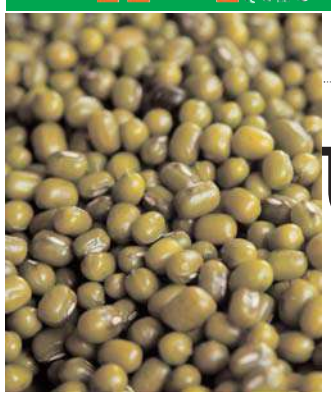

सीहोर के किसानों ने दवा, बीज विक्रेताओं से उधार में सामान लिया अब उन्हें किया जा रहा परेशान

एक माह बाद भी किसानों को नहीं मिला मूंग का पैसा, 236 करोड़ का भुगतान अटका

सीहोर। जागत गांव हमार

प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत इस वर्ष की गई मूंग खरीदी में किसान परेशान दिखाई दे रहा है। बीते 5 अगस्त तक हुई मूंग की खरीदी में अब तक किसानों के खातो में भुगतान नहीं पहुंच सका है, जिससे किसान अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहा है। इस वर्ष समर्थन मूल्य पर मूंग का विक्रय करने के लिए 29448 किसानों ने पंजीयन कराकर 27301 किसानों ने स्लॉट बुक की थी, अंतिम तिथि तक 26022 किसान ने 717340 क्विंटल मूंग का विक्रय भी कर दिया था। किसानों को भरोसा था कि जिस तरह से मूंग की तिथि आगे बढ़ाई गई हैं वैसे ही सरकार किसानों के खातो में सात दिन के अंदर उपज का भुगतान भी कर देगी। लेकिन मूंग का विक्रय किये हुए 25 दिन से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन हजारों किसानों के खातो में अब तक मूंग का भुगतान प्राप्त नहीं हो सका है। जिससे किसान प्रतिदिन बैंकों व अधिकारियों के चक्कर काटता दिखाई दे रहा है।

आधे किसानों का भुगतान अटका- इस वर्ष प्राइज सपोर्ट स्कीम के तहत शासन द्वारा 24 जून से 31 जुलाई तक ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी किए जाने के आदेश जारी किए गए थे। लेकिन मूंग उपार्जन का कार्य खरीदी से 15 देरी से शुरू हुआ। इसके चलते किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ा। खरीदी शुरू भी हुई और किसानों ने स्लॉट बुकिंग भी की, लेकिन गोदामों पर स्लॉट बुकिंग फुल होने से कई किसान अंतिम तिथि तक मूंग का विक्रय करने से वंचित रह गए। जिन किसानों ने मूंग का विक्रय किया इनमें से आधे किसानों के खाते में भी मूंग का भुगतान हो सका है।

खरीदी हो गई 7 लाख क्विंटल

इस वर्ष एनसीसीएफ द्वारा मूंग की खरीदी की गई, जिसमें केंद्र सरकार का लक्ष्य सीहोर जिले में 4 लाख क्विंटल तय किया गया था। लेकिन किसानों के विरोध के बाद तिथि में संशोधन कर पांच दिन और खरीदी की गई, जिससे खरीदी का आंकड़ा 7 लाख क्विंटल को पार कर गया। केंद्र सरकार द्वारा तय लक्ष्य के अनुसार किसानों को 61.48 फीसदी याने 613 करोड़ में से 377 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अब भी 236 करोड़ का भुगतान किसानों को होना शेष है। ऐसे में किसान लगातार बैंकों में अपने खातो की जानकारी ले रहा है, लेकिन खातो में राशि ना आने से वह मायूस दिखाई दे रहा है। किसानों को भुगतान कब तक प्राप्त होगा, इस बारे में अधिकारी भी किसानो को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं।

अधिकारी भी नहीं दे रहे जवाब

मूंग का विक्रय कर भुगतान का इंतजार कर रहे किसान शोभाराम मुकाती, पर्वत सिंह उईके, जय प्रकाश पंवार, अनिरुद्ध मालवीय व दिनेश पंवार बताते हैं कि हमने खरीदी शुरू होने के 10 दिन के अंदर ही मूंग का विक्रय केंद्रों पर कर दिया। हमारे बाद जिन किसानों ने मूंग तुलाया उनके खाते में मूंग की राशि आ चुकी है, लेकिन हमारे खाते अब भी खाली है। मूंग पैदा करने के लिए जिन दवा, बीज विक्रेताओं से उधार में सामान लिया अब वह हमें परेशान कर रहे हैं। कई किसानों को तो मजदूरी का भी भुगतान करना है, लेकिन राशि ना होने से सब परेशान हैं। किसानों ने बताया कि भुगतान कब तक आएगा। इस बारे में अधिकारी भी सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं।

गोदाम संचालक बरत रहे लापरवाही

इस वर्ष मौसम की अनुकूलता के चलतें क्षेत्र में मूंग का उत्पादन भी विपुल हुआ और दाने में भी बोल्ड पका। बावजूद इसके खरीदी में सर्वेयरों व सुपरवाइजरों की संदिग्ध भूमिका के चलतें कई गोदामों पर किसानों के पंजीयनों पर व्यापारिक सौदा हुआ, जिसमें 68912 हजार क्विंटल मूंग जांच के दौरान 25 गोदामों में नान एफएक्यू पाया गया। इसके चलते जिला उपार्जन समिति द्वारा गोदामों की स्टेक का रिजेक्ट कर उसका अपग्रेडेशन कराए जाने के निर्देश दिए गए। लेकिन कुछ गोदाम संचालक मूंग की छनाई में भी लापरवाही कर हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। गोदाम संचालकों को मूंग की छनाई में लाखों रुपए की चपट लग रही है, जिससे वह इस मामले में फर्जी रिपोर्ट बनाकर जिला उपार्जन समिति को सौंपने की तैयारी में है।

अब तक जिलेभर में हुई मूंग खरीदी में 613 करोड़ में से 377 करोड़ का रुपए का भुगतान किसानों को हो चुका है। शेष किसानों को भी शीघ्र ही भुगतान प्राप्त होगा। भुगतान कब तक किसानों के खातों में आएगा यह शासन स्तर का मामला है।

केके पांडे, उप संचालक कृषि

किसान मोबाइल से घर बैठे कर सकेंगे पंजीयन, पंजीयन 19 से 4 अक्टूबर तक किया जाएगा

किसानों से समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार और बाजरा भी खरीदेगी प्रदेश सरकार

भोपाल। जागत गांव हमार

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन के लिए किसान 19 सितम्बर से 4 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि निर्धारित समय में पंजीयन करा लें, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। उन्होंने बताया है कि किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। किसान स्वयं के मोबाईल से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे। किसानों को पंजीयन केन्द्रों में लाईन लगाकर पंजीयन कराने की समस्या से मुक्ति मिलेगी। किसानों के मोबाइल से पंजीयन करने की सुविधा के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। पंजीयन की नि:शुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर, तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर तथा एमपी किसान एप पर भी की गई है।

पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था

पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था एमपी ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्ति यों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर की गई है। इन केन्द्रों पर पंजीयन के लिये शुल्क राशि प्राप्त करने के संबंध में कलेक्टर निर्देश जारी करेंगे। प्रति पंजीयन के लिये 50 रुपए से अधिक शुल्क निर्धारित नहीं किया जाएगा। किसान पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज एवं किसान के आधार कार्ड एवं अन्य फोट पहचान पत्रों का समुचित परीक्षण कर उनका रिकार्ड रखा जाना अनिवार्य होगा। सिकमी/बटाईदार/कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन की सुविधा केवल सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन सहकारी संस्था द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों पर उपलब्ध होगी। इस श्रेणी के शत-प्रतिशत किसानों का सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा।

उपार्जित फसल के भुगतान के लिए बैंक खाता

किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में किसी कारण से समस्या उत्पन्न होने पर किसान द्वारा पंजीयन में उपलब्ध कराए गए बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा। किसान पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और इ्फ्स्स्ट कोड की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। अक्रियाशील बैंक खाते, संयुक्त बैंक खाते एवं फिनो, एयरटेल, पेटीएम, बैंक खाते पंजीयन में मान्य नहीं होंगे। पंजीयन व्यवस्था में बेहतर सेवा प्राप्त करने के लिए यह जरूरी होगा कि किसान अपने आधार नंबर से बैंक खाता और मोबाईल नंबर को लिंक कराकर उसे अपडेट रखें। सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि जिला और तहसील स्तर पर स्थापित आधार पंजीयन केन्द्रों को क्रियाशील रखा जाए ताकि किसान वहां जाकर आसानी से अपना मोबाईल नंबर एवं बायोमेट्रिक अपडेट करा सके। इस कायद्ग के लिए पोस्ट ऑफिस में संचालित आधार सुविधा केन्द्र का भी उपयोग किया जा सकता है। आधार नंबर से बैंक खाता लिंक कराने के लिए बैंकों के साथ भी समन्वय आवश्यक होगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते के सत्यापन हेतु पंजीयन के दौरान ही 1 रूपये का ट्रांजेक्शन मध्यप्रदेश राज्य आपूर्ति निगम द्वारा ई-उपार्जन पोर्टल के माध्यम से कराया जाएगा।

आधार नंबर का वेरिफिकेशन

पंजीयन कराने और फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। वेरिफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओटीपी से या बायोमेट्रिक डिवाईस से किया जा सकेगा। किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि किसान के भू-अभिलेख के खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही उक्त पंजीयन मान्य होगा।

किसानों को करें एसएमएस

विगत रबी एवं खरीफके पंजीयन में जिन किसानों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं, उन्हें एसएमएस से सूचित करने के निदेज्श दिये गये हैं। गांव में डोडी पिटवाकर ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर पंजीयन सूचना प्रदर्शित कराने तथा समिति/ मंडी स्तर पर बैनर लगवाने के निर्देश भी दिये गये हैं। किसान पंजीयन की सभी प्रक्रियाएं समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।

फसलों में कीट रोगों के एकीकृत नियंत्रण के लिए तकनीकी जानकारी दी

उद्यानिकी फसलों से अधिक आय

शिवपुरी। जागत गांव हमार

शिवपुरी जिले में फसल विविधता एवं उद्यानिकी फसलों से अधिक आय प्राप्त करने तथा नगदी फसलों को उगाने के लिए उन्नत कृषि जानकारी के लिए कृषकों के लिए उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जिला शिवपुरी द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र, शिवपुरी पर राज्य योजनान्तर्गत जिले के अंदर एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन जिले के कोलारस, शिवपुरी, पोहरी एवं नरवर विकासखंड के 60 कृषकों की सहभागिता में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ कृषक पंजाब सिंह गुर्जर, डॉ. पुनीत कुमार प्रमुख कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी एवं बालमुकुन्द मिश्रा, सहायक संचालक उद्यान द्वारा मां सरस्वती पूजन के साथ किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित कृषकों को उद्यानिकी फसलों में कीट रोगों के एकीकृत नियंत्रण के लिए तकनीकी जानकारी जेसी गुप्ता, वैज्ञानिक (पौध संरक्षण) द्वारा बताई गई। शिवपुरी जिले में नवाचार गतिविधियों में मूल्यवान फसल स्ट्रॉबेरी की उन्नत खेती की जानकारी पॉवर पाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से जिले में कृषि जलवायु अंतर्गत किए गए परीक्षण सह प्रदर्शन अनुभवों के साथ वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एमके भार्गव द्वारा दी गई। साहित्य का वितरण भी किया गया। शिवपुरी जिले में उद्यानिकी फसलों की सघन खेती जिसमें फल, सब्जी एवं मसाला उत्पादन के लिए उन्नत कृषि तकनीकियों तथा फसल विविधता में टमाटर जैसी फसल में गेंदा फसल की अंतर्वर्ती खेती 16:1 (16 कतार में टमाटर एवं 1 कतार में गेंदा) से जैविक इंजीनियरिंग के माध्यम से फसल को होने वाले लाभों के बारे में जानकारी कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रमुख डॉ. पुनीत कुमार द्वारा दी गई।

किसानों की प्रशिक्षण उपरांत जिज्ञासाओं का भी समाधान किया गया

उद्यानिकी फसलों के प्रसंस्करण तथा प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना से लाभ लेते हुए प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने एवं अन्य उद्यानिकी योजनाओं की जानकारी सहायक संचालक उद्यान बालमुकुन्द मिश्रा द्वारा कृषकों को बतलाई गई। कृषि विज्ञान केन्द्र, के वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों द्वारा उद्यानिकी के लिए उपयोगी बांस उत्पादन डॉ. एनके कुशवाहा तथा हाईटेक हार्टिकल्चर यंत्रीकरण की जानकारी डॉ. एएल बसेड़िया द्वारा दी गई। प्रशिक्षण में इन्द्रवीर ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी द्वारा कृषकों को तकनीकी जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र की प्रदर्शन इकाइयों का अवलोकन कराया गया। कृषकों की प्रशिक्षण उपरांत जिज्ञासाओं का भी समाधान किया गया।

अब गांवों में बनाए जाएंगे पीएम किसान समृद्धि केंद्र

सीएम मोहन का निर्देश- ज्वार, बाजरा,मक्का की फसलों को भी किया जाए प्रोत्साहित

किसानों को एक जगह पर मिलेगी सभी जानकारी

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी गांवों में पीएम किसान समृद्धि केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान इस संबंध में अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना की जाएगी। सोयाबीन की फसल के साथ ज्वार, बाजरा, मक्का की फसलों को भी प्रोत्साहित किया जाए। किसानों को पीएम किसान समृद्धि केंद्रों के द्वारा खाद, बीज, कृषि उपकरण, मिट्टी परीक्षण के साथ विभिन्न प्रकार की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा 5 ऑइल मिल की स्वीकृति दी गई है। प्रदेश में 235 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय नवाचार प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। एक जिला-एक उत्पाद अंतर्गत नवीन सहकारी समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि जिला सहकारी बैंको को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए योजना तैयार करें।

बुरहानपुर और खरगोन में शक्कर कारखाने

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ के कार्यों और मध्यप्रदेश राज्य विपणन संघ की विभिन्न लेनदारियों के संबंध में बैठक में चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि अपेक्स बैंक में राज्य शासन द्वारा 142 करोड़ रुपए की अंशपूंजी निवेशित की है। बैंक में आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। प्रदेश की 38 जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित कोर बैंकिग सोल्यूशन प्रणाली पर कार्यरत हैं। अपेक्स बैंक को 131.83 करोड़ का संचित लाभ हुआ है। अपेक्स बैंक द्वारा राज्य शासन को विगत 4 वर्ष में 12 करोड़ 10 लाख राशि का लाभांश दिया है। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम अच्छे ढंग से कराए जा रहे हैं। बुरहानपुर और खरगोन में शक्कर कारखाने कार्य कर रहे हैं।

कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव के वैज्ञानिकों ने किया जागरुक

राजनगर में फलदार पौधों का वितरण किसानों को किया गया प्रशिक्षित

छतरपुर। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र, नौगांव, छतरपुर की वरिष्ठ वैज्ञानिक एवम प्रमुख डॉ. वीणा पाणी श्रीवास्तव के दिशा निर्देश में वैज्ञानिक डॉ. कमलेश अहिरवार द्वारा गत दिवस ग्राम पीरा, तहसील राजनगर में किसानों को फलदार पौधों का वितरण एवं पौध रोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर किसानों को उन्नत किस्म के मुनगा, नींबू जैसे फलदार पौधे वितरित किए गए। पौधरोपण कार्यक्रम के साथ ही किसानों को उनके खेतों की मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने हेतु जागरूक किया गया।

डॉ. अहिरवार ने किसानों को फलदार पौधों की देखभाल, सिंचाई विधियों, जैविक खाद के उपयोग एवं कीट प्रबंधन पर भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने किसानों की आय में वृद्धि के लिए फल खेती को एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। इसके अलावा, उन्होंने फलों की खेती में लगने वाले प्रमुख रोग एवं कीटों की पहचान और उनके नियंत्रण के प्रभावी उपायों के बारे में प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम में उपस्थित रोहित मिश्रा (वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता) ने खरीफ फसलों में मौसमी चुनौतियों का सामना करने के लिए

समसामयिक कार्ययोजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से खरीफ मौसम में फसलों की समय पर बुआई, सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन और कीट नियंत्रण के उपायों पर जोर दिया। कृषक प्रशिक्षण के दौरान किसानों की विभिन्न समस्याओं को ध्यान से सुना गया, और विशेषज्ञों द्वारा समाधान बताए गए। डॉ. अहिरवार ने फसल उत्पादन को बेहतर बनाने के लिए उन्नत तकनीकियों और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करने पर बल दिया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के अन्य अधिकारी और ग्राम पीरा के उत्साहित किसानों ने कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों से अवगत कराकर उनके उत्पादन एवं आय में सुधार करना था, जिसे सभी किसानों ने सराहा।

खेतों में मृदा परीक्षण करने के बाद ही खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए

खरीफ की प्रमुख फसलों में पोषक तत्वों के बारे में किसानों को तकनीकी सलाह

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार, वैज्ञानिक डॉ. आईडी सिंह, डॉ. आरके प्रजापति, डॉ. एसके सिंह, डॉ. यूएस धाकड़, डॉ. सतेन्द्र कुमार, डॉ. एसके जाटव एवं जयपाल छिगारहा द्वारा किसानों को खरीफ फसलों में पोषक तत्वों की कमी एवं पहचान के बारे में निम्न जानकारी दी गयी।

नाइट्रोजन - पुरानी पत्तियों का पीला पड़ना और पौधे की वृद्धि कम होना।

फास्फोरस - पुरानी पत्तियों पर लाल और बैंगनी रंग के साथ सूखना।

पोटाश - पुरानी पत्तियों की शिखायें और किनारों का जलना या झुलसना।

कैल्शियम - नई पत्तियों की कालिकाओं का शिकुड़ना और धीरे-धीरे मर जाना।

मैग्नीशियम - पुरानी पत्तियों से ऊपर हरा रंग जाना शुरू होना।

सल्फर - नई पत्तियों की शिराओं का रंग हल्का हरा होना और बढ़वार कम होना।

आयरन - नई पत्तियों का पीला पड़ना और शिराओं का हरा होना।

मैग्नीज - नई पत्तियों के ऊतक भरने से भूरे, काले धब्बे दिखना।

जिंक - नई पत्तियों की शिराओं में पीली परत का पड़ना या उतरना और पुरानी पत्तियों का मरना।

कॉपर - नई पत्तियों का पीला या सफेद होना।

बोरान - नई पत्तियों की कलिका किनारे से हल्की हरी और धीरे-धीरे झुलस कर मर जाना।

मोलिब्डेनम - नई पत्तियों का अगला शिरा सूखना और मुड़ना।

क्लोरीन - पत्तियों के किनारे मुरझाना या झुकाना।

इन सभी पोषक तत्वों की कमी से नुकसान के साथ-साथ पोषक तत्वों की अधिकता होने पर भी फसल को नुकसान होता है। अत: सभी कृषकों को पोषक तत्व (उर्वरक) खेत में डालने से पहले मृदा परीक्षण अवश्य करना चाहिए। मृदा परीक्षण सामान्यत: रबी की फसल काटने के बाद गर्मियों (अप्रैल-मई) में मिट्टी का नमूना लेकर कराया जाता है परंतु यदि आवश्यक हो तो खरीफ की फसल काटने के बाद (अक्टूबर-नवम्बर) में जब खेत खाली हो तब मृदा का नमूना एकत्रित करके मृदा परीक्षण करवा सकते हैं। अत: किसानों को सलाह दी जाती है कि मृदा परीक्षण करने के बाद ही खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे मृदा के स्वास्थ्य में सुधार होगा एवं किसानों का खाद एवं उर्वरकों पर व्यय न्यूनतम होगा।

मध्य प्रदेश के किसानों के सामने नई और अजीब मुसीबत

एक्सप्रेस-वे की तेज रोशनी से लंबे हो रहे सोयाबीन के पौधे! रतलाम के किसानों की जिला प्रशासन से मुआवजे की गुहार

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश को देश के एक ऐसे राज्य के तौर पर जाना जाता है, जहां पर सोयाबीन की खेती जमकर होती है। इस वजह से कुछ लोग इसे सोया स्टेट भी कहते हैं। सोयाबीन की खेती यहां के किसानों के लिए भी फायदे का सौदा साबित होती रही है। लेकिन अब सोयाबीन की खेती करने वाले किसान एक नई मुसीबत से दो-चार हो रहे हैं। आपको सुनकर अजीब लगेगा लेकिन यहां पर एक्सप्रेस-वे पर लगी चमकीली लाइट्स सोयाबीन की खेती के लिए नई परेशानी बन गई है। किसानों का कहना है कि तेज रोशनी की वजह से पौधे बढ़ रहे हैं लेकिन फलियां जस की तस बनी हुई हैं। दरअसल, मध्य प्रदेश में किसान पहले से ही सोयाबीन की गिरती कीमतों और येलो मोजैक वायरस से परेशान थे। इस वायरस की वजह से किसानों को सोयाबीन की फसल को नष्ट करना पड़ा है। वहीं कुछ किसान कम दाम मिलने से भी निराश हैं। इन सबके बीच ही अब रतलाम के नीमन और उपलई गांव में सोयाबीन के किसान से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे की वजह से अजीबो-गरीब समस्या का सामना करने को मजबूर हैं। उनकी मानें तो एक्सप्रेस वे पर लगी तेज रोशनी वाली हाई मास्ट लाइट सोयाबीन की फसलों को आराम नहीं करने दे रही। यहां के किसान पिछले तीन सालों से सोयाबीन की फसल खराब होने से परेशान हैं। नीमन और उपलई गांव के किसानों का दावा है की दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के हाई मास्ट की तेज रोशनी की वजह से सोयाबीन में अफलन की समस्या आ गई है। किसानों ने इसके लिए जिला प्रशासन से गुहार भी लगाई है।

नितिन गडकरी तक से अपील

किसानों की धमकी के बाद कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। गांव के किसानों की मानें तो सिर्फ सोयाबीन ही नहीं, बल्कि मक्का, गेहूं और सब्जियों की फसल में भी इसी तरह की समस्या आ रही है। किसानों की मानें तो यह सबकुछ 8 लेन की लाइटों की वजह से ही हो रहा है क्योंकि पेड़ की छाया में दबे हुए फसल के पौधों पर फलियां लग रही हैं। जबकि रोशनी पड़ने वाले हिस्से में अफलन की स्थिति है। किसानों ने कहा है कि एसडीएम, कलेक्टर और विधायक सहित केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी चिट्ठी लिखी गई है लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।

आंदोलन की दी धमकी

जावरा के पास से होकर गुजरने वाले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे नीमन और उपलई गांवों से निकलता है। इस जगह एक्सप्रेस-वे पर होटल, अस्पताल के साथ ही एंट्री और एग्जिट प्वाइंट भी बना हुआ है। इसकी वजह से यहां पर बड़ी-बड़ी हाई मास्ट और फ्लड लाइट्स लगाई गई हैं। इस रोड के 200 मीटर के रेडियस में सौ डेढ़ सौ बीघा जमीन पर सोयाबीन की फसल असामान्य तरीके से लंबी हो गई है। पौधे काफी बड़े और घने जरूर हो गए हैं, लेकिन इसमें फूल और फलिया नहीं लगी हैं। अफलन की समस्या से तीन साल से जूझ रहे किसानों ने इस बार आंदोलन करने की चेतावनी दी है।

किसानों ने की मुआवजे की मांग

वहीं कृषि विभाग के सहायक संचालक बिका वास्कले केवीके के वैज्ञानिकों साथ जब निरीक्षण पर पहुंचे तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही पाया। उनका कहना था कि 24 घंटे लगातार रोशनी मिलने की वजह से पौधों में असामान्य बढ़वार हो गई है। इसी वजह से अब इसमें फलियां कम या नहीं आई हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने भी माना है कि फसल पर तेज रोशनी का प्रभाव पड़ा है। किसानों की मांग है कि एक्सप्रेस-वे पर लगी लाइटों को बंद किया जाए और उन्हें खराब हुई फसल का मुआवजा भी दिया जाए।

तितलियों के समर सर्वे में 43 दुर्लभ तितलियों की खोज

मप्र में तितलियों की समृद्ध दुनिया, बैतूल भारतीय पारिस्थितिक का हॉट-स्पॉट

बैतूल। जागत गांव हमार

दक्षिण बैतूल वनमंडल में पहली बार आयोजित तितलियों का समर सर्वेक्षण एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आया है। 19 जून से 24 जून 2024 तक चले इस सर्वेक्षण में 43 प्रकार की तितलियों की पहचान की गई, जिसमें कई प्रजातियां ऐसी हैं जो मध्यप्रदेश में बहुत कम देखी जाती हैं। डीएफओ विजयानन्तम टीआर की पहल पर यह सर्वेक्षण आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य तितलियों की विविधता और उनके पारिस्थितिक महत्व को समझना और उसे दस्तावेजीकृत करना था, ताकि बैतूल की प्राकृतिक धरोहर को संजोया जा सके।

दक्षिण बैतूल के वन प्राकृतिक सुंदरता के संरक्षक

बैतूल के जंगल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के लिए प्रसिद्ध हैं, और यह सर्वेक्षण इस बात का प्रमाण है कि यहां के पेड़-पौधे कई दुर्लभ और असामान्य तितलियों को आकर्षित करते हैं। सर्वेक्षण के दौरान हेस्पेरिडे परिवार की स्पॉटेड स्मॉल फ्लैट तितली भी देखी गई, जो इससे पहले केवल पचमढ़ी में रिकॉर्ड की गई थी। इसका बैतूल में मिलना संकेत देता है कि इस क्षेत्र में तितलियों की और भी कई असामान्य प्रजातियां पाई जा सकती हैं। इसके अलावा स्लेट फ्लैश, कॉमन ट्रीब्राउन, कॉमन शॉट सिल्वरलाइन, कॉमन पॉमफ्लॉय, डबल बैंडेड जूडी, कॉमन थी-रिंग, कॉमन हेज ब्लू और कॉमन माइम स्वैलोटेल जैसी प्रजातियों का भी दस्तावेजीकरण किया गया।

तितलियों की समृद्ध दुनिया

भारत, अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है, और यहां तितलियों की लगभग 1,500 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि दुनिया भर में पाई जाने वाली 17,000 तितली प्रजातियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनमें से कई प्रजातियां स्थानिक हैं, यानी वे केवल भारत में ही पाई जाती हैं, जिससे भारत तितली विविधता का एक हॉटस्पॉट बनता है। मध्यप्रदेश में भी 150 से अधिक प्रजातियों की तितलियों को रिकॉर्ड किया गया है, जो कि इस राज्य की जैव विविधता का एक अनमोल हिस्सा है।

इन दुर्लभ तितलियों की हुई खोज

मोटल्ड इमिग्रेंट, पायनियर, लाइम स्वालोटेल, प्लेन टाइगर, पेंटेड लेडी, कॉमन ग्रास येलो, लेमन पंसी, पेल ग्रास ब्लू, स्पॉटलेस ग्रास येलो, कॉमन हेज ब्लू, कॉमन सार्जेंट, जेब्रा ब्लू, स्पॉट स्वॉड्ज्टेल, स्पॉटेड स्माल फ्लैट, कॉमन शॉट सिल्वरलाइन, ग्रेट एगफ्लाई, डिंगी बुशब्राउन, बैरोनेट, कॉमन थी-रिंग, कॉमन माइम स्वालोटेल, चॉकलेट पंसी, कॉमन ट्रीब्राउन, कॉमन पामफ्लाई, स्लेट फ्लैश, स्माल ग्रास येलो, चेस्टनट-स्ट्रिक्ड सैलर, कॉमन लेपडज, डार्क ग्रास ब्लू, लेमन इमिग्रेंट, डेनाइड एगफ्लाई, कॉमन कास्टर, इंडियन जेज़ेबेल, ब्लू पंसी, ग्रेट एगफ्लाई, कॉमन क्रो, कॉमन रोज स्वालोटेल, इंडियन जेज़ेबेल, स्ट्रिप्ड टाइगर, कॉमन मोरमॉन स्वालोटेल, ग्राम ब्लू, प्लम जूडी/डबल-बैंडेड जूडी, कॉमन सैलर, ब्लू पियरोट्स/स्पॉटेड पियरोट।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना ने किया आयोजन

मध्य प्रदेश में ई-पंचायत को मजबूत करने के लिए ई-पंचायत कार्यशाला

भोपाल। जागत गांव हमार

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) पटना ने एब्सोल्यूट ग्राम्या प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर गत दिवस भोपाल के एक निजी होटल में विकासशील ई-पंचायत के माध्यम से संगत ग्रामीण शासन, स्वास्थ्य और कौशल विकास को सशक्त बनाना शीर्षक की कार्यशाला का सफल आयोजन किया। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश में ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा।

प्रो.टीएन सिंह, आईआईटी पटना के निदेशक और फाउंडेशन फॉर इनोवेटर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (फिस्ट) के अध्यक्ष ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण शासन को आगे बढ़ाने में फिस्ट और आईआईटी पटना की विकासात्मक भूमिका पर टिप्पणी की। प्रो. सिंह ने कहा कि फिस्ट के साथ सहयोग के माध्यम से आईआईटी पटना ग्रामीण शासन के लिए अभिनव समाधानों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ई-पंचायत पहल एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे प्रौद्योगिकी शासन में अंतराल को पाट सकती है और सार्थक परिवर्तन ला सकती है। हम इस प्रयास का समर्थन करने और अधिक समावेशी और कुशल शासन मॉडल की दिशा में काम करने के लिए उत्साहित हैं। कार्यशाला का उद्देश्य ई-पंचायत प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण शासन, स्वास्थ्य और कौशल विकास को बढ़ाना था। ग्रामीण शासन में डिजिटल परिवर्तन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता है।

ई-पंचायत प्रणाली ग्रामीण प्रशासन का आधुनिकीकरण करने के दृष्टिकोण की एक आधारशिला है। डिजिटल प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके, शासन को अधिक पारदर्शी, कुशल और सुलभ बना सकते हैं। यह पहल न केवल सार्वजनिक सेवाओं के वितरण को बढ़ाएगी, बल्कि ग्रामीण समुदायों को अपने स्वयं के विकास में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त भी करेगी। कार्यशाला में राज्य की प्रभावी शासन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा वितरण में सुधार के प्रति समर्पण को उजागर किया गया। सत्र की शुरुआत एब्सोल्यूट ग्राम्य के सीएमडी डॉ. पंकज शुक्ला के स्वागत भाषण से हुई, जिन्होंने कार्यक्रम के उद्देश्यों और ई-पंचायत पहल के महत्व को रेखांकित किया।

महाराष्ट्र-कर्नाटक में एमएसपी पर सरकारें करेंगी सोयाबीन की खरीदी

अब सरकार पर टिकी मप्र के किसानों की नजर

भोपाल। जागत गांव हमार

सोयाबीन को लेकर बड़ी खबर है। सोयाबीन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ये बड़ा फैसला तब हुआ है, जब देश में सोयाबीन के गिरते दामों को लेकर देशभर में घमासान मचा हुआ है। मसलन, बीते रोज ही मध्य प्रदेश के अशोकनगर में किसानों ने सोयाबीन की अर्थी निकाल कर गिरते दामों पर मातम मनाया था। हालांकि इसी बीच मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में देश में नंबर वन की पोजिशन कब्जाने में कामयाब हुआ है। सोयाबीन पर घमासान से जुड़ी इस लंबी भूमिका के बाद सोयाबीन पर हुए फैसले की बात करते हैं। असल में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलांगाना में एमएसपी (मूल्य समर्थन) पर सोयाबीन की खरीद करने का ऐलान किया है। इससे एमएसपी पर सोयाबीन की खरीद सुनिश्चित हो सकेगी, लेकिन इस सरकारी ऐलान के बाद सोयाबीन पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में जारी घमासान और तेज होने की उम्मीद है। मसलन, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में सोयाबीन के दाम बढ़ाने के प्लान का सरकार ने ऐलान किया है, लेकिन सवाल ये है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में सोयाबीन के गिरते दामों का समाधान क्या होगा, इसको लेकर किसान चिंतित हैं।

उत्पादन में राज्यों की हिस्सेदारी- सोयाबीन उत्पादन में नंबर वन के खिताब को लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में संघर्ष होता रहता है। कुल जमा ताजे आंकड़ों से समझे तो मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को पछाड़ कर सोया प्रदेश के खिताब पर कब्जा किया है। कृषि मंत्रालय के तरफ से बीते रोज जारी आंकड़ों के अनुसार 5.47 मिलियन टन सोयाबीन उत्पादन के साथ मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, जिसकी कुल उत्पादन में हिस्सेदारी 41.92 फीसदी है। जबकि महाराष्ट्र 5.23 मिलियन टन सोयाबीन उत्पादन के साथ दूसरे नंबर पर है, जिसकी कुल उत्पादन में हिस्सेदारी 40.01 फीसदी है। राजस्थान 8.96 फीसदी यानी 1.17 मिलियन टन उत्पादन के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके बाद कर्नाटक, तेलांगाना की हिस्सेदारी है।

मध्यप्रदेश में सोयाबीन पर घमासान

मध्य प्रदेश को बीते रोज ही सोया प्रदेश का खिताब मिला है, लेकिन इस सोया प्रदेश के खिताब के साथ ही मध्य प्रदेश में सोयाबीन पर घमासान शुरू हो गया है। सोयाबीन पर घमासान के पीछे की कहानी ये है कि मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत देश की दूसरी मंडियों में सोयाबीन का दाम 3800 से 4000 रुपए क्विंटल चल रहे हैं, जबकि सोयाबीन का एमएसपी 4892 रुपए क्विंटल है। कुल जमा किसानों को प्रति क्विंटल 1000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों को होने वाले नुकसान का ये हाल तब है, जबकि नई फसल की आवक शुरू नहीं हुई है। किसानों का कहना है कि नई फसल की आवक शुरू होने पर दामों में और गिरावट होगी, जबकि मौजूदा समय में सोयाबीन के ये दाम पिछले 13 सालों में सबसे निचले स्तर पर हैं। कुल जमा सोयाबीन के इन गिरते दामों से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक के किसान परेशान हैं। इस बीच मध्य प्रदेश में किसान संगठनों ने सोयाबीन के दाम 6 हजार रुपये क्विंटल तय करने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है।

महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना ने किया खुश

मध्य प्रदेश में सोयाबीन पर घमासान जारी है। इस बीच केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय ने महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में सोयाबीन की खरीद एमएसपी पर करने का ऐलान किया है। कृषि मंत्रालय ने अपने अधिकृत एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए जानकारी दी है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में केंद्र सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों को मूल्य समर्थन योजना के तहत सोयाबीन की खरीद के लिए दिशा निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को सोयाबीन की फसल बेचने में कोई कठिनाई न हो और उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिल सके।

किसानों को ये होगा फायदा

एमएसपी यानी मूल्य समर्थन योजना का क्रियान्वयन केंद्र सरकार राज्यों में करती हैं, जिसके तहत किसी फसल के दाम एमएसपी से कम होने की स्थिति में केंद्र सरकार अधिसूचित नोडल एजेंसी के माध्यम से उस फसल की खरीद एमएसपी पर करती है। उस फसल की एमएसपी पर तब तक खरीद सुनिश्चित की जाती है, जब तक उसके दाम बाजार में संतोषजनक स्तर तक ना बढ़ जाएं। इससे किसानों को फायदा होता है। मसलन, कम दाम में फसल बेचने को मजबूर किसानों को एमएसपी मिलता है तो वहीं बाजार में दाम बढ़ने पर भी बेहतर लाभ मिलता है।

मप्र-राजस्थान में समाधान

महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में सोयाबीन की एमएसपी पर खरीद का ऐलान केंद्र सरकार ने किया है। इससे मध्य प्रदेश के किसानों में नाराजगी है। इसको लेकर किसान नेता राहुल राज ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया है। साथ ही मध्य प्रदेश में एमएसपी पर खरीद करवाने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में सोयाबीन पर राजनीति तेज होते हुए दिख रही है, जबकि राजस्थान में सोयाबीन का मामला अभी ठंडा पड़ा है। कुल जमा मध्य प्रदेश के किसान सोयाबीन के मुद्दे पर पोस्टर बॉय बनते हुए दिख रहे हैं तो वहीं राजनीति भी पीक पर है। ऐसे में समझा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अगर सोयाबीन पर महौल गरमाता है तो भावांतर योजना से किसानों के नुकसान की भरपाई का ऐलान राज्य सरकार को करना होगा।

-चावल और कपास की सबसे अधिक किस्म

सरकार ने जारी की फसलों की 184 वैरायटी की अधिसूचना

भोपाल। जागत गांव हमार

सरकार ने आज फसलों की 184 वैरायटी या हाईब्रिड को जारी करने की अधिसूचना जारी कर दी। इसमें चावल, गेहूं, बार्ली, मक्का, बेबीकॉर्न, ज्वार, चीना, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, चना, अरहर, मूंग, बरसीम, गन्ना, जूट और कपास फसलें प्रमुख हैं। अधिसूचित की गई इन वैरायटी में चावल की किस्में सबसे अधिक हैं। इन वैरायटी की अधिसूचना केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से जारी की गई है। इसका नोटिफिकेशन सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स के तहत जारी किया गया है। फसलों की इन वैरायटी को अलग-अलग राज्यों में खेती के लिहाज से जारी किया गया है। फसलों की किस्मों को अधिसूचित करने वाली सब कमेटी ने मक्के की एक वैरायटी को खारिज कर दिया जिसका नाम जवाहर मक्का (बी) 2201 (सीएचसी-2201) है। यह खुले में परागण होने वाली किस्म है जिसे दिल्ली, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के लिए सिफारिश की गई थी। इसका प्रस्ताव अधूरा रहा, इसलिए सब-कमेटी ने इसकी अधिसूचना को रद्द कर दिया।

इन फसलों को मिली हरी झंडी-

अधिसूचना में सबसे अधिक चावल की 44 वैरायटी हैं जो अलग-अलग राज्यों के लिए जारी की गई हैं। इसके बाद गेहूं की ब्रेड और ड्यूरम की एक-एक वैरायटी हैं। जौ की एक वैरायटी है। मक्के की 13 वैरायटी को हरी झंडी दी गई है। इसके अलावा ज्वार की एक, चीना की एक, तिल की एक, सोयाबीन की दो, मूंगफली की दो, सूरजमुखी की तीन, चने की तीन, अरहर की दो, मसूर की तीन, मटर की चार, बरसीम की दो, चारा ज्वार की दो, चारा मक्का की चार, चारा मोती बाजरा की चार, चारा जई की चार, लूसर्न घास की एक, गन्ने की पांच, जूट की दो, अनाज अमरनाथ की छह और कपास की 61 किस्में हैं। कुछ वैरायटी को नोटिफाई करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है। चावल की 27, गेहूं की छह, मक्के की 15, बाजरा की चार, रागी की पांच, छोटा बाजरा की दो, चना की छह, मटर की एक, मसूर की एक, मूंग की छह, उड़द की एक, राजमा की दो, गन्ने की चार, कपास की दो, तंबाकू की दो, चिया सीड और ईसबगोल की एक-एक वैरायटी हैं।

भोपाल वन विहार में अंर्तराष्ट्रीय गिद्ध दिवस पर कार्यशाला

भोपाल। अंर्तराष्ट्रीय गिद्ध दिवस वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, विहार वीथिका में गिद्ध संरक्षण एवं संर्वधन विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में भोपाल शहर के आस-पास संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित गौशालाओं के संचालक/प्रबंधक सम्मिलित हुए। कार्यशाला में गौ संचालकों को गिद्ध संरक्षण एवं संर्वधन विषय पर जानकारी के साथ-साथ गायों के उपचार में डायक्लोफेनिक दवा का उपयोग न करने एवं अन्य विषयों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई गई। कार्यशाला के उद्देश्यों पर मीना अवधेशकुमार शिवकुमार, संचालक, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल द्वारा प्रकाश डाला गया। मो. खालीक, भोपाल बर्ड्स, भोपाल द्वारा गिद्ध प्रजाति एवं उनके महत्व पर प्रकाश डाला, जैनब खान, बायोलॉजिस्ट, गिद्ध संवर्धन केन्द्र, केरवा, भोपाल द्वारा गिद्ध संर्वधन केन्द्र में किस प्रकार से गिद्धों को संरक्षित किया जाता है, इसके बारे में जानकारी दी।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)